



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्तूबर, 1978
आश्विन 14, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2690/सत्रह-वि०-1--70-1978
लखनऊ, 6 अक्तूबर, 1978

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आवकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आवकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1978)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह, धारा 1, 2, 5 और 6 के सिवाय जो तुरन्त प्रवृत्त होंगी, 1 मई, 1972

धोषणा

2—एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम, मादक पेयों और स्वास्थ्य के हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध सुनिश्चित करने की संविधान के अनुच्छेद 47 में अधिकृत राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
4, सन् 1910
की धारा 20 का
संशोधन

3--उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी और 1 मई, 1972 को निकाली गई समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 24 अप्रैल, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि वह उपधारा निकाली न गई होती तो कोई अपराध न होती।

धारा 37-क क
प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 37-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायगी, अर्थात्--

"37-क—(1) उपधारा (4) क उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या परिवहन करने, कब्जे में रखने या उसका परिवहन निषिद्ध होगा।
उसका उपभोग करने का निषेध।

(2) धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अपराधों के, यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायें, अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा, किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबन्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जायें, निषिद्ध होगा।

(3) राज्य में मद्य निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, इस निमित्त भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है, अर्थात् :—

(क) किसी क्षेत्र का स्वरूप, यथा—

(एक) सरकार का मुख्यालय, या

(दो) विद्या केन्द्र, या

(तीन) तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या

(चार) पर्वतीय क्षेत्र, या

(पांच) औद्योगिक क्षेत्र, या

(छः) मद्यनिषेध वाले क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र, या

(सात) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की वस्ती, या

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टितल और जीवन-स्तर भी है, या

(ग) स्थानीय जनमत, या

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोकहित में सारवात हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों की, जिनके आधार पर, कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित है।

(4) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह क्षेत्र जिसमें उपधारा (1) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, और जिसमें उपधारा (2)

के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखन या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाय और वह दिनांक जिससे किसी क्षेत्र में मद्य निषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (4) में किमी. बात के होते हुए भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को, निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये, कब्जे में रखने, या उक्त उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है :—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य ;

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी ;

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री ;

(घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सालय महाविद्यालय, जिनमें औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो ;

(ङ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति ;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य निषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण ;

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औद्योगिक या धार्मिक प्रयोजन।

(6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (5) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(7) उपधारा (4) में अभिविष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य निषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके सम्बन्ध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा 35 में दी गयी कृती बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

(8) जहां उपधारा (7) के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाय वहां लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निवेदा दे"।

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किय गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होता।

5—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और सर्वेव से विधिमान्य समझी जायेगी मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय में प्रवृत्त थे।

बंधीकरण

निरसन और
अपवाद

6--(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2690/XVII-V-1—70-78

Dated Lucknow, October 6, 1978

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1978), as passed by the Legislature and assented to by the President on October 3, 1978 :

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SECOND [AMENDMENT] ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 30 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furtherto amend the United Provinces Excise Act, 1910

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Second Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1972, except sections 1, 2, 5 and 6 which shall come into force at once.

Declaration.

2. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the policy of the State towards securing prohibition of the consumption, except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health as laid down in Article 47 of the Constitution.

Amendment of
section 20 of
U. P. Act no. IV
of 1910.

3. In section 20 of the United Provinces Excise Act, 1910 (hereinafter referred to as the principal Act) as amended by Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1978, sub-section (2), shall be omitted and be deemed to have been omitted with effect from May 1, 1972 :

Provided that no Act done or omission taking place during the period commencing on May 1, 1972 and ending with April 24, 1978, which would not be an offence but for such omission shall constitute an offence punishable under the principal Act.

Substitution of
section 37-A.

4. For section 37-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“37-A. (1) Subject to the provisions in sub-section (4), the import or export of any intoxicating into or from Uttar Pradesh or any part thereof or the transport of any intoxicant shall be prohibited.

Prohibition of
import, export,
transport, posses-
sion or consump-
tion of intoxi-
cants.

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 30
सन् 1978

(2) Notwithstanding anything contained in section 20, but subject to the provision of sub-section (4), the possession or consumption by any person or class of persons or subject to such exceptions, if any, as may be specified, by all persons in Uttar Pradesh or in any specified area or areas thereof, of any intoxicant shall absolutely or subject to such conditions as may be specified, be prohibited.

(3) In pursuance of the policy of gradual extension of prohibition in the State and having regard to the administrative convenience, the State Government may from time to time select different areas in that behalf after taking into account any one or more of the following factors, namely:—

- (a) the character of an area as—
 - (i) the seat of Government; or
 - (ii) a seat of learning; or
 - (iii) a place of pilgrimage or of religious importance; or
 - (iv) hill area; or
 - (v) an industrial area ; or
 - (vi) contiguous to dry area; or
 - (vii) inhabited by Scheduled Castes or Scheduled Tribes; or
- (b) the general economic condition of the local population, including their level of nutrition and standard of living; or
- (c) the local public opinion ; or
- (d) any other relevant factor which in the opinion of the State Government is material in the public interest :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to require the State Government to recite in its order, the considerations on the basis of which a particular area is selected at any time for the enforcement of prohibition.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3), the area to which the prohibition on import, export or transport of any intoxicant under sub-section (1) and on possession or consumption of any intoxicant under sub-section (2) extends and the date on which the prohibition in any area comes into force, shall be such as the State Government may, from time to time, specify by notification.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in relation to any prohibition area, the State Government may, either by rules or by general or special order, make any exemption or relaxation in respect of the possession, consumption, import, export or transport of the intoxicants mentioned in the notification under sub-section (4) or any of such intoxicant by or for purposes of—

- (a) members of the defence services ;
- (b) foreigners visiting or residing in the prohibition area ;
- (c) travellers through the prohibition area ;
- (d) district hospitals or medical colleges requiring any intoxicant for medicinal purposes ;
- (e) persons holding licences under sections 17, 18, 21 and 24 ;
- (f) consignment from, to, or passing through the prohibition area by rail, road or air ;
- (g) industrial, scientific, educational, medicinal or religious purposes.

(6) In relation to any exemption or relaxation that may be made under sub-section (5), the State Government may either by rules or by general or special order, provide for the grant of pass or permit by such authority as may be specified.

(7) Upon the issue of a notification referred to in sub-section (4), the authority granting a licence under this Act may in so far as it relates to a prohibition area cancel it forthwith without notice, and it shall

thereupon remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect of the unexpired period of the licence, and refund any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof, less the amount, if any, due to the State Government, but no compensation shall in respect of such cancellation be payable to the licensee, anything contained in section 35 notwithstanding.

(8) Where any licence is cancelled under sub-section (7) the licensee shall dispose of the intoxicants in his possession in such manner as the State Government or the Excise Commissioner may by general or special order direct."

Provided that no act done or omission taking place during the period commencing on May 1, 1972 and ending with June 25, 1978 which would not be an offence but for such substitution shall constitute an offence punishable under the principal Act.

Validation.

5. Notwithstanding any judgement, decree or order of any court to the contrary anything done or purporting to have been done, and any action taken or purporting to have been taken under the provisions of the principal Act, before the commencement of this section shall be valid and be deemed always to have been valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

6. (1) The Uttar Pradesh Excise (Third Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA.
Sachiv.